

पहले विलेज एक्शन प्लान बनेगा उज्जैन में 'यंग थिंकर्स फोरम' कॉन्क्लेव

कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कलेक्टरों को मिले निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता **भोपाल, 8 अक्टूबर**. प्रदेश में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सभी जिले शीघ्र ही प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान तैयार करेंगे. ये प्लान तैयार करने के बाद इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना भी जरूरी होगा. इसी विलेज एक्शन प्लान के आधार पर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार होगा और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के



विषयों एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया. ये तय किये गये प्लान के अलावा था. इस सत्र को लेकर प्रजेंटेशन प्रमुख सचिव जनजाति कार्य गुलशन बामरा ने दिया. उन्होंने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान में 14 हजार 40 लक्षित गांव के 10 हजार 893 विलेज एक्शन प्लान बन चुके हैं. इन गांवों में 11 हजार 394 आदि सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं. आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान जन धन, जाति प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जारी किए गए उनकी संख्या 17 लाख 70 हजार 745 है। प्रजेंटेशन में बताया गया कि आयुष्मान कार्ड जारी करने में शिवपुरी, मैहर,

- ▶ डिस्ट्रिक्ट प्लान के आधार पर बनेगा स्टेट प्लान
- ▶ जल्द एक्शन प्लान पर होगा अमल

आधार पर स्टेट एक्शन प्लान तैयार होगा. इस प्रकार तैयार हुए प्लान का नई दिल्ली में बाकायदा प्रजेंटेशन होगा. यहां सर्वश्रेष्ठ प्लान को पुरस्कृत किया जाएगा.

कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जनजातीय विकास कार्यों, आदि कर्मयोगी अभियान, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार अधिनियम संबंधी

निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कराने की अपेक्षा

अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल ने जिला कलेक्टरों से वन अधिकार अधिनियम के तहत दिसंबर 2025 तक पूर्व के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर निराकरण करने की अपेक्षा की. उन्होंने कहा कि सामाजिक सामुदायिक वन संधारण के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता के लिए जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करें और लंबित दावों का निराकरण करें. वन ग्रामों के राजस्व गांव में परिवर्तन करने के लिए अपनाई गई आदर्श प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश जिलों को दिये, जिससे सभी वन अधिकार-पत्र धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके. वन अधिकार के दावों का निराकरण करने में भोपाल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर छतरपुर ने उच्च प्रदर्शन किया है.



रायसेन, कटनी और भिंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. लंबित जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जबलपुर, रायसेन और सिवनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. सभी जिलों से

बेहतर कार्य वाले जिलों ने दिया प्रजेन्टेशन

आदि सेवा केंद्रों की स्थापना में बड़वानी खरगोन, नरसिंहपुर, सीहोर और इंदौर जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. सत्र में बैतूल जिले ने आदि कामयोगी अभियान शिवपुरी ने पीएम जनमन आवास, शाहडोल ने पीएम जनमन आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र एवं आयुष्मान कार्ड वितरण संबंधी कार्य एवं बालाघाट ने वन अधिकार दावों के निराकरण पर प्रजेंटेशन दिया.

अधोसंरचनात्मक कार्य जैसे हॉस्टल निर्माण, सड़क निर्माण, आंगणवाड़ी भवन निर्माण, बहुउद्देशीय सेंटर निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये.

रास्ता खुला रखने के नाम पर मांगे थे 25 लाख

- ▶ लोकयुक्त ने सरपंच पति और सहयोगी को रिवाज लेते पकड़ा

नवभारत न्यूज **इंदौर/खरगोन**. इंदौर लोकयुक्त टीम ने बुधवार को खरगोन जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को एक लाख रुपए की रिश्त लेते रंगेहाथ पकड़ा. दोनों आरोपी सरकारी भूमि के उपयोग और रास्ता खुला रखने के नाम पर सेवानिवृत्त फौजी से 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे.

ट्रैप दल के कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि



आवेदक अंतिम जैन, निवासी समर्थ सिटी इंदौर, भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने अपने मित्र स्वर्णिम माहेश्वरी के साथ दिसंबर 2023 में ग्राम छोटी कसरवाद जिला

खरगोन में कृषि भूमि खरीदी थी. उक्त भूमि से लगी शासकीय जमीन पर कच्ची सड़क बनी है, जो उनके खेत का एकमात्र रास्ता है. आरोप है कि ग्राम पंचायत छोटी कसरवाद के वाटरमैन

आवर्तित करवाएंगे, जिससे उसका रास्ता बंद हो जाएगा. बाद में दोनों ने रास्ता खुला रखने के एवज में 25 लाख रुपये की रिश्त की मांग की. शिकायत मिलने पर लोकयुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन कराया, जो सही पाया गया. इसके बाद बुधवार को ट्रैप दल गठित किया. आवेदक से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए लेते समय दोनों आरोपियों को टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

एमपी में नकली दवाओं का बोलबाला

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का आरोप

विशेष संवाददाता **भोपाल, 8 अक्टूबर**. कांग्रेस के मीडिया प्रभारी डॉ. मुकेश नायक ने बुधवार को आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में सफ़ाई की जा रही

- ▶ प्रदेशवासी दवा खरीदते समय सतर्क रहें



स्वास्थ्य व्यवस्था इन नकली दवाओं के कारण गंभीर संकट में है. डॉ. नायक ने आरोप लगाया कि

कई दवाएं नकली और घटिया गुणवत्ता की हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की

भाजपा सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी है और दोषी दवा कंपनियों के खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं है. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे दवा खरीदते समय सतर्क रहें और उनकी असलियत अवश्य जांचें. कांग्रेस नेता के अनुसार, सरकार की लापरवाही अपारधिक उदासीनता के समान है, जिससे राज्यभर में लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ी हुई है.

एक नजर में

त्योहार के पहले मुरैना में अवैध पटाखे बरामद

मुरैना. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस ने एक मकान से अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया है. अंबाह पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि अंबाह के जंगमा रोड स्थित एक मकान में विक्रय करने के लिए अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है. पुलिस ने कल देर रात मकान पर छापा मारकर जब मकान की तलाशी ली तो वहां पर अवैध पटाखों का एक बड़ा जखीरा मिला. पुलिस ने मौके पर ही पटाखे जब्त कर मकान मालिक बुद्धाराम के विरुद्ध दिस्पोकट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार जब्त पटाखों की कीमत पचास हजार रुपए से अधिक बताई गई है.

दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत

शिवपुरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में दो आदिवासी बच्चों की गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई. मायापुर पुलिस सूत्रों ने बताया कि ग्राम मानिकपुर के पास तलेया में दो बच्चे डूब गए थे. परिजन बच्चों को तलेया से निकालकर जिला चिकित्सालय लाए, जहां बुधवार को तड़के उनकी मृत्यु हो गई. पिछर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत शर्मा ने बताया कि दोनों की पहचान सन्नू आदिवासी (7) एवं सोमपाल आदिवासी (5) के रूप में हुई है.

अवैध शराब ले जा रही कार डिवाइडर से टकराई

सागर. जिले में एक लजरी कार से अवैध शराब का परिवहन करते पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपए आंकी गई है. सानोधा पुलिस के अनुसार देर रात एक सफेद रंग का एसयूवी वाहन दमोह से सागर की ओर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर आ रहा था. नाकाबंदी के दौरान वाहन तेज रफ्तार में आता दिखा, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया, जिससे वाहन डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त

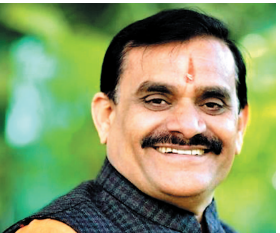
खजुराहो-बनारस के बीच दौड़ेगी वंदे भारत

पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई उड़ान देने की तैयारी

खजुराहो, 8 अक्टूबर. मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को इस दिवाली केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है. खजुराहो से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है.

बुंदेलखंड को मिला दिवाली का तोहफा

यह घोषणा खजुराहो सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा (बी.डी. शर्मा) की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई फोन पर बातचीत के बाद हुई. सांसद शर्मा ने इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री द्वारा बुंदेलखंड को दिया गया दिवाली गिफ्ट बताया है. सांसद शर्मा ने बताया कि खजुराहो से बनारस के बीच वंदे भारत ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी. कुछ माह पूर्व उन्होंने रेल मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर इस संबंध



में पत्र सौंपा था. शर्मा के आग्रह पर रेल मंत्री ने सकारात्मक पहल करते हुए इस मार्ग पर ट्रेन चलाने की सहमति दी थी. मंगलवार को हुई फोन पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने सांसद को बताया कि ट्रेन शुरू करने के आदेश एक-दो दिन

में जारी कर दिए जाएंगे. शर्मा ने कहा कि यह ट्रेन बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विकास और समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी. सांसद शर्मा ने कहा कि बाबा मतंगेश्वर की नगरी खजुराहो से बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस को जोड़ने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगी. इससे रोजगार, व्यापार और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.

स्थानीयों में खुशी, सांसद ने बताया आभार

घोषणा के बाद स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई. उनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मध्यप्रदेश का गौरवशाली पर्यटन नवशर पर और चमकेगा. सांसद वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है. उन्होंने कहा, यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के विकास की नई रफ्तार है.

कफ सिरप कांड सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है: स्वास्थ्य मंत्री

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: शुक्ल

छिंदवाड़ा/परासिया, 08 अक्टूबर. छिंदवाड़ा में किडनी फेल से हो रही लगातार बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बयान दिया कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है.

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के परासिया दौरे के बाद अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य निचिकास मंत्री डॉ राजेंद्र शुक्ल ने परासिया का दौरा करते हुए पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल चाल जाना. स्वास्थ्य मंत्री डॉ शुक्ल परासिया के खजरी अंतुमोरडोंगरी और



बड़कुई में पीड़ित परिवारों से मिले, उसके पश्चात उन्होंने परासिया स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने परासिया अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि परासिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल भवन है, लेकिन सुविधाएं नदारत हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने शीघ्र परासिया अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहिया कराए जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार कफ सिरप से हो रही मौत के मामले में एक्शन ले रही है. उन्होंने भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन लोगों से करने की अपील करते हुए कहा कि वे केवल उन कफ सिरप का उपयोग करें जिसमें सरकार की ओर से एडवाइजरी दिखाई गई है तथा वे ऐसे कफ सिरप को बिल्कुल उपयोग न करें जिसमें एडवाइजरी जारी नहीं की गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने आईएम ए का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपना काम करें. सरकार अपना काम कर रही है. कानून को अपना काम करने दे. जो निर्दोष होगा वह छूट जाएगा. लेकिन इस मामले में दोषी को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा.

चार लाख में एक मां की गोद खरीदना चाहती है सरकार: सिंघार

छिंदवाड़ा/परासिया, 08 अक्टूबर. जिले में जहरीले कफ सिरप से मासूम बच्चों की हो रही मौत के मामले में प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पे है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए छिंदवाड़ा का दौरा किया.

परासिया के इंटक हाल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए देकर एक मां की गोद खरीदना चाहती है? अगर सरकार सही में इस मुद्दे पर संवेदनशील है तो ऐसे पीड़ित परिवार जिनके बच्चे की मौत हो चुकी है उन्हें इलाज का पूरा खर्चा दे. नहीं तो वह परिवार जीवन भर कर्ज के बोझ में दबे रहेंगे. इतनी मौत के बाद सरकार आज तक



जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई है. छोटे बच्चे पर सरकार कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है. आज दिनांक तक सरकार उस कंपनी पर शिकंजा नहीं कस पाई है जिसके द्वारा यह जहरीला कफ सिरप बनाया गया. सरकार का पूरा सिस्टम फेल है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पीड़ित परिवारों के

घर पहुंच कर केवल उनका हाल-चाल जान रहे हैं ऐसे बेशर्म मंत्री को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार नॉट में सो रही है. जब तक दर्जनों बच्चों की जान नहीं गई, तब तक बच्चों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. यह लापरवाही अक्षम्य है.